

मूक पत्रिका

निष्पक्ष, निर्भीक, स्वतंत्र आवाज...

वर्ष - 02 अंक - 240 बेमेतरा, शनिवार 25 अप्रैल 2026 रायपुर एवं बेमेतरा से प्रकाशित कुल पेज - 08 मूल्य - 5 रुपये डाक पंजीयन- दुर्गा/1743290201/2025-27

संक्षिप्त समाचार

नदी में नहाने गए तीन सगे भाई-बहन बने हादसे का शिकार, डूबने से तीनों की मौत

बड़वानी। मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले के वरला थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम देवली में एक दर्दनाक हादसा हो गया। यहां अनेर नदी में नहाने गए तीन सगे भाई-बहन एक-दूसरे को बचाने के चक्कर में डूब गए। मृतकों की पहचान 10 वर्षीय राधा, 8 वर्षीय राजवीर और 6 वर्षीय जयवीर के रूप में हुई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार तीनों बच्चे परिवार के साथ ग्राम बोलवा में मामा के घर गए थे। तीनों बच्चे अनेर नदी में नहाने गए, जहां अचानक हादसा हो गया। एक बच्चा डूबने लगा तो बाकी दो उसे बचाने गए और तीनों पानी में डूब गए। कड़ी मशक़त के बाद स्थानीय लोगों ने तीनों बच्चों के शव बरामद किए। उन्हें तुरंत ध्वली प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने तीनों को मृत घोषित कर दिया। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिए गए। इस घटना से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई है और गांव में मातम का माहौल छा गया है। पुलिस ने मामले में मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है।

ट्रक की टक्कर से बाइक सवार दो युवकों की मौत, ग्रामीणों ने किया चक्काजाम

बालोद। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले के नेशनल हाईवे-30 पर एक भीषण सड़क हादसे में बाइक सवार दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। यह हादसा दल्लीराजहरा थाना क्षेत्र के जमहिटोला प्लाजा और गुजरा गांव के बीच हुआ। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची है। वहीं हादसे की जानकारी मिलते ही घटना स्थल पर ग्रामीणों की भीड़ जुट गई है और शवों को सड़क पर रखकर हाईवे पर चक्काजाम कर मुआवजे की मांग कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक, तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार दोनों युवक ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। हादसे में एक मृतक की पहचान डोमेन्द्र यादव निवासी ग्राम गुजरा के रूप में की गई है, जबकि दूसरे युवक का चेहरा बुरी तरह कुचल जाने के कारण उसकी पहचान अभी तक नहीं हो सकी है।

नितिन नवीन ने दिलाई सदरयता, खिलाई मिठाई

सांसद राघव चड्ढा समेत बागी सांसदों ने ज्वाइन की बीजेपी...

नई दिल्ली/ एजेंसी

आम आदमी पार्टी के भीतर भूचाल आया हुआ है. राघव चड्ढा समेत आम आदमी पार्टी के बागी सांसद बीजेपी मुख्यालय पहुंचकर पार्टी अध्यक्ष बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात कर रहे हैं. राघव के साथ संदीप पाठक और अशोक मित्तल भी मौजूद हैं. आप के इन बागी नेताओं ने आधिकारिक तौर पर बीजेपी ज्वाइन कर ली है. इस मौके पर नितिन नबीन ने सभी को पार्टी की सदस्यता दिलाई और मिठाई खिलाकर पार्टी में उनका स्वागत किया. बता दें कि, राघव चड्ढा ने आम आदमी पार्टी यानी आप छोड़ने का ऐलान कर दिया है. आप पार्टी छोड़ने के साथ ही राघव चड्ढा ने बीजेपी में शामिल करने का भी ऐलान

किया है. राघव चड्ढा ने संदीप पाठक और अशोक मित्तल के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भाजपा में शामिल होने का ऐलान किया. साथ ही राघव ने आप के दो तिहाई सांसद और दिल्ली में नेता विपक्ष भी बीजेपी में शामिल होने का दावा किया है. इनमें स्वाती मालिवाल, हरभजन सिंह, राजेंद्र गुप्ता, विक्रम साहनी, संदीप पाठक, राजेंद्र गुप्ता का नाम शामिल है. संदीप पाठक और अशोक मित्तल के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए, कसांसद राघव चड्ढा ने कहा, हमने फैसला किया है कि हम, राज्यसभा में आप के 2/3 सदस्य, भारत के संविधान के प्रावधानों का इस्तेमाल करते हुए खुद को बीजेपी में मिला लेंगे. उन्होंने आगे कहा कि आपको मैंने अपने खून-पसीने से सींचा और अपनी जवानी के 15 साल दिए,



अब अपने सिद्धांतों, मूल्यों और मूल नैतिकता से भटक गई है. अब यह पार्टी देश के हित में नहीं, बल्कि अपने निजी फ़ायदे के लिए काम करती है. पिछले कुछ सालों से, मुझे यह महसूस हो रहा था कि मैं गलत पार्टी में सही आदमी हूं.

इसलिए, आज हम यह ऐलान करते हैं कि मैं आप से खुद को अलग कर रहा हूं और जनता के करीब जा रहा हूं. आम आदमी पार्टी के पास राज्यसभा में कुल 10 सांसद थे, जिनमें 7 पंजाब और 3 दिल्ली से हैं. हालांकि, आज पार्टी को उस वक्त

जबरदस्त झटका लगा, जब तीन प्रमुख सांसदों- राघव चड्ढा, संदीप पाठक और अशोक मित्तल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पार्टी छोड़ दी और औपचारिक रूप से बीजेपी में शामिल हो गए. इन तीनों सांसदों ने अपने इस्तीफे के साथ ही यह दावा किया है कि राज्यसभा में पार्टी के दो-तिहाई से ज्यादा सांसद अब उनके (बीजेपी) साथ हैं. इससे पहले दिल्ली विधानसभा चुनावों के दौरान स्वाति मालीवाल भी बगावती रुख अपना चुकी थीं. अब राघव, संदीप और अशोक के जाने से अरविंद केजरीवाल की राज्यसभा में ताकत आधी से भी कम रह गई है. इस बड़ी टूट ने आम आदमी पार्टी के भविष्य और उसकी सांगठनिक एकता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. इस बगावत के पीछे दिल्ली चुनाव में हुई पार्टी की हार एक बड़ी वजह रही है.

बीजेपी ने फिर से पंजाबियों के साथ किया धक्का

आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद रहे राघव चड्ढा समेत संदीप पाठक और अशोक मित्तल भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। उन्होंने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन से मुलाकात की और भाजपा में आधिकारिक रूप से शामिल हुए। इस मौके पर नितिन नबीन ने सभी को फूलों को लहू खिलाकर स्वागत भी किया। आम आदमी पार्टी में एंडी बड़ी टूट के बाद पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल का पहला रिएक्शन सामने आया है। अरविंद केजरीवाल ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया है। इस पोस्ट में लिखा, बीजेपी ने फिर से पंजाबियों के साथ किया धक्का। भले ही पोस्ट छेदा हो लेकिन इसके मायने काफ़ी बड़े है।



खुशी हुई एसआईआर के बीच

बंगाल चुनाव में रिकॉर्ड वोटिंग से सीजेआई सूर्यकांत गदगद हुए.....

नई दिल्ली/ एजेंसी

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले चरण में हुई रिकॉर्ड वोटिंग से सीजेआई सूर्यकांत गदगद है। बंगाल चुनाव में रिकॉर्ड मतदान पर भारत मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने खुशी जाहिर की है। सीजेआई सूर्यकांत ने कहा है कि राज्य में 92 प्रतिशत से ज्यादा मतदान देखकर खुशी हुई है। दरअसल सीजेआई ने यह टिप्पणी पश्चिम बंगाल के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर मामले में 71 लोगों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान की। सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि भारत के नागरिक के तौर पर मुझे



लोगों को बड़-चढ़ कर मतदान करते देख खुशी हुई। यह लोकतंत्र की मजबूती के लिए जरूरी है। सीजेआई सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल एम पंचौली की बेंच को बताया गया कि गुरुवार (23 अप्रैल, 2026) को बंगाल विधानसभा

चुनाव के फर्स्ट फेज में 92 प्रतिशत से भी ज्यादा वोटिंग हुई है। इस पर सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि भारत के नागरिक के तौर पर मुझे लोगों को बड़-चढ़ कर मतदान करते देख खुशी हुई। यह लोकतंत्र की मजबूती के लिए जरूरी है। सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि इस तरह के मामलों के समाधान के लिए संबंधित पक्षों को कलकत्ता हाईकोर्ट का रुख करना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि रोज़ाना सामने आने वाले ऐसे मुद्दों को हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश प्रशासनिक स्तर पर भी देख सकते हैं। और जरूरत पड़ने पर न्यायिक हस्तक्षेप भी किया जा सकता है।

हिमाचल में बढ़ने लगा

पारा : जिला ऊना में सीजन का सबसे गर्म दिन, पारा 38.7 डिग्री

शिमला। हिमाचल प्रदेश में गर्मी ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। प्रदेश के मैदानी इलाकों में पारा तेजी से चढ़ रहा है, जिससे सामान्य जनजीवन प्रभावित होने लगा है। बुधवार को ऊना जिला प्रदेश में सबसे गर्म रहा। यहां अधिकतम तापमान 38.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो इस सीजन का अब तक का सबसे अधिक तापमान है। लगातार बढ़ रही गर्मी के बीच एक ताजा पश्चिमी विक्षोभ 24 अप्रैल से सक्रिय होने वाला है, जिससे प्रदेशवासियों को चिलचिलाती धूप से कुछ राहत मिल सकती है। मौसम विभाग की ओर से जारी पूर्वानुमान के अनुसार 24 अप्रैल को ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों में हल्की बारिश या हिमपात हो सकता है।

लखीमपुर खीरी में बड़ा

सड़क हादसा, ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से पांच की मौत

लखीमपुर। पड़ुआ थाना क्षेत्र में ढखेरवा, गजियापुर कैलाशपुरी मार्ग पर बोझिया पेट्रोल पंप के पास गुरुवार को बड़ा सड़क हादसा हो गया। मुंडन संस्कार के लिए जा रही लोगों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली अचानक पलट गई, जिससे मौके पर चीख-पुकार मच गई। बड़ी संख्या में श्रद्धालु मुंडन कार्यक्रम के लिए ट्रैक्टर-ट्रॉली से बहराइच के सुजौली थाना क्षेत्र के कारीकोट देव स्थान जा रहे थे। सभी मृतक और घायल शारदानगर थाना क्षेत्र के निवासी हैं। 22 घायलों में कई की हालत बेहद गंभीर है। घायलों में कई की हालत गंभीर होने के कारण मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका जताई जा रही है।

महिलाओं की सुरक्षा, हमारी प्राथमिकता

अमित शाह बोले-अब भय जाने वाला है, भरोसा आने वाला है...

नई दिल्ली/ एजेंसी

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव का सियासी माहौल लगातार गरमाता जा रहा है। पहले चरण में हुए रिकॉर्ड मतदान ने जहां चुनावी मुकाबले को नया मोड़ दिया है, वहीं अब सभी राजनीतिक दल दूसरे चरण की तैयारी में पूरी ताकत झोंकते नजर आ रहे हैं। 29 अप्रैल को होने वाले दूसरे चरण से पहले राजधानी कोलकाता में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। इसी बीच शुक्रवार को भाजपा के शीर्ष नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कोलकाता में प्रेस वार्ता



किया, इस दौरान उन्होंने बंगाल चुनाव के लिए पहले चरण में हुए रिकॉर्ड मतदान के लिए राज्य की जनता का धन्यवाद दिया। साथ ही कहा कि बंगाल की जनता ने परिवर्तन के लिए वोट किया है। उन्होंने पहले चरण में हुए रिकॉर्ड मतदान के लिए बंगाल की

जनता को बधाई दिया। अमित शाह ने कहा कि कल के मतदान में बंगाल की जनता ने परिवर्तन के लिए वोट दिया, जिसके लिए मैं उनका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं। उन्होंने कहा कि इस बार राज्य में चुनाव बेहद शांतिपूर्ण तरीके से हुए हैं, जो अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। इसके साथ ही अमित शाह ने असम और ओडिशा में भाजपा के शासन के अलावा पश्चिम बंगाल में पार्टी की संभावनाओं पर कहा कि पांच मई के बाद 'अंग, बंग और कलिंग' में सरकारें होंगी। प्रेस वार्ता के दौरान अमित शाह ने आगे चुनाव आयोग की पूरी टीम की सराहना की।

रेत कारोबार को लेकर विवाद की आशंका

कांग्रेस नेता के घर में घुसकर गोलीबारी एक बेटे की मौत दूसरे की हालत गंभीर

जांजगीर-चांपा। जांजगीर-चांपा जिले के बिरा थाना क्षेत्र के करही गांव में गुरुवार देर रात एक सनसनीखेज वारदात हुई। कांग्रेस नेता सम्मेलाल कश्यप के बड़े बेटे आयुष कश्यप की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस घटना से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। देर रात करीब 12:30 बजे तीन नकाबपोश बदमाश सम्मेलाल कश्यप के घर में घुस आए। सम्मेलाल सीमेंट-रेत व्यवसायी और पूर्व ब्लॉक कांग्रेस उपाध्यक्ष हैं। बदमाशों ने अचानक फायरिंग शुरू कर दी। उन्होंने परिवार के



सदस्यों को निशाना बनाया। हमले में आयुष कश्यप को दो गोलियां लगीं, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। आयुष के छोटे भाई आशुतोष कश्यप को भी गोली



लगी है। उसे गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका उपचार चल रहा है। मृतक की बहन प्रेरणा कश्यप ने बताया कि हमलावर नकाब पहने

हुए थे। उन्होंने सीधे आयुष को निशाना बनाया और पहले उसे गोली मारी। इसके बाद छोटे भाई पर भी फायरिंग की गई। प्रेरणा ने यह भी बताया कि लगभग एक सप्ताह पहले कुछ युवक आयुष के बारे में पूछताछ करने गांव आए थे। घटना की सूचना पर पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। प्रभारी पुलिस अधीक्षक निवेदिता पाल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उमेश कश्यप, साइबर दल और न्यायिक विज्ञान दल मौके पर पहुंचे। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरों की जांच शुरू कर दी है।

क्या बंगाल में महिलाएं और बेटियां सुरक्षित हैं

पहले चरण के मतदान ने सत्ताधारी दल की नींदें उड़ाई आरजी कर मामले में दोषियों को मिलेगी सजा-मोदी

कोलकाता/ एजेंसी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल में एक बहुत बड़ा और कड़ा बयान दिया है। उन्होंने साफकहा है कि आरजी कर अस्पताल में हुए रेप और मर्डर केस की साजिश में शामिल किसी भी रसूखदार या अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। पीएम मोदी ने जनता को भरोसा दिलाया है कि अगले महीने जब राज्य में भाजपा की सरकार बनेगी, तो हर एक अपराधी को खोजकर उसे सजा दी जाएगी। यह खबर बंगाल के उन सभी आम लोगों के

लिए बहुत बड़ी उम्मीद है जो लंबे समय से इस दर्दनाक मामले में न्याय की मांग कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने यह बात शुक्रवार को उत्तर 24 परगना जिले के पानीहाटी विधानसभा क्षेत्र में एक विशाल चुनावी रैली के दौरान कही। यह वही पानीहाटी इलाका है जहां अगस्त 2024 में कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में जान गंवाने वाली महिला डॉक्टर का पुराना घर है। इस चुनाव में भाजपा ने उसी पीड़ित महिला डॉक्टर की मां स्वप्ना देबनाथ को इस सीट से अपना उम्मीदवार



बनाया है। मोदी ने कहा कि स्वप्ना देबनाथ ने अपनी बेटी को देश की सेवा करने के लिए डॉक्टर बनाने में जीवन भर संघर्ष किया, लेकिन

जुल्म का हिसाब होगा। प्रधानमंत्री ने मौजूदा सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि पिछले 15 वर्षों में इस सरकार ने बंगाल की पहचान को पूरी तरह से नष्ट कर दिया है। राज्य में लगातार घुसपैठियों को लाया जा रहा है और उन्हें यहां बसाया जा रहा है। ये घुसपैठिए बंगाल की जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं और यहां के स्थानीय लोगों का रोजगार छीन रहे हैं। एक तरफ सरकार का भारी भ्रष्टाचार है और दूसरी तरफ घुसपैठियों का जुल्म है। इस कारण से बंगाल के युवाओं को नौकरी की तलाश में अपने घर

छोड़कर बाहर जाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। राज्य में कोई नया निवेश नहीं आ रहा है और पुरानी फैक्ट्रियां भी बंद होकर दूसरी जगह जा रही हैं। रैली में पीएम मोदी ने महिलाओं की सुरक्षा और उनके हकों पर खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार के राज में बेटियां बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं हैं। लेकिन जब भाजपा की सरकार आएगी, तो कोई भी रेपिस्ट या अपराधी सुरक्षित नहीं बचेगा। महिलाओं को मजबूत बनाने के लिए भाजपा के कार्यकर्ता घर-घर जाकर मातृ शक्ति भरोसा कार्ड बांट रहे हैं।

ममता बनर्जी का भाजपा पर तीखा वार

बंगाल जीतने के बाद दिल्ली कब्जा कर लूंगी

कोलकाता। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शुक्रवार को भाजपा पर हमला किया। उन्होंने कहा कि मेरा जन्म बंगाल में हुआ है और मैं बंगाल में ही मरूंगी। बंगाल जीतने के बाद, मैं दिल्ली पर कब्जा कर लूंगी। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा 'भाजपा के लिए काम करने वाले सभी लोगों के नाम सूचीबद्ध हैं। आपने भाजपा पृष्ठभूमि के आधार पर लोगों को लाया है और उसी के अनुसार अधिकारियों की नियुक्ति की है। याद रखिए, आप हमें हराने की क्षमता नहीं रखते। हम अन्याय के खिलाफ लड़ते हैं, हम अपने



अधिकारों के लिए लड़ते हैं। मेरा जन्म बंगाल में हुआ है और मैं बंगाल में ही मरूंगी। बंगाल जीतने के बाद, मैं दिल्ली पर कब्जा कर लूंगी। मुझे सत्ता नहीं चाहिए, मुझे दिल्ली में भाजपा का विनाश चाहिए, न केवल बंगाल में विनाश होगा, बल्कि भाजपा को दिल्ली से भी हटाना होगा।

संपादकीय

किसी भी संविधान संशोधन विधेयक को पारित कराने के लिए लोकसभा में दो-तिहाई बहुमत की जरूरत होती है, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद सरकार जरूरी समर्थन हासिल नहीं कर सकी। इसमें कोई दोराय नहीं कि विधायिका में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के लिए सरकार और सभी विपक्षी दलों को एक ईमानदार इच्छाशक्ति के साथ काम करना चाहिए। मगर यही मुद्दा जब राजनीतिक लाभ उठाने का जरिया बनने लगता है, तब इस पर सवाल उठने लगते हैं। बीते हफ्ते सरकार ने महिला आरक्षण से जुड़ा 131वां संशोधन

विधेयक पेश किया, लेकिन जरूरी समर्थन न मिल पाने की वजह से वह लोकसभा में गिर गया। गौरतलब है कि किसी भी संविधान संशोधन विधेयक को पारित कराने के लिए लोकसभा में दो-तिहाई बहुमत की जरूरत होती है, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद सरकार जरूरी समर्थन हासिल नहीं कर सकी। हालांकि इस बार परिसीमन विधेयक में संशोधन के लिए जिस तरह महिला आरक्षण का मसला भी जुड़ा हुआ था, उसमें इस मुद्दे पर दो-तिहाई सांसदों को अपने पक्ष में खड़ा कर पाना सरकार के लिए मुश्किल था। यानी पहले ही यह माना जा रहा था

कि लोकसभा में संशोधन विधेयक पारित करना मुमकिन नहीं हो पाएगा। इसके बावजूद यह विचित्र है कि सरकार ने इस पर जोर-आजमाइश करने की कोशिश की। दरअसल, इस संशोधन विधेयक का उद्देश्य यह बताया गया था कि इससे लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण सुनिश्चित किया जा सकेगा। साथ ही, 2026 से पहले की जनगणना के आधार पर राज्यों में सीटों के परिसीमन की इजाजत दी जाएगी और लोकसभा में सीटों की संख्या 543 से बढ़ा कर 850 की जाएगी।

मगर चूंकि परिसीमन के साथ उलझे इस मुद्दे पर सरकार को जरूरी संख्या बल का समर्थन नहीं मिल सका, इसलिए अब भाजपा विधानसभा चुनावों के प्रचार के दौरान यह आरोप लगाने की कोशिश कर सकती है कि विपक्षी पार्टियां महिलाओं को भागीदारी देने का समर्थन नहीं करतीं। सवाल है कि महिलाओं की विधायिका में आरक्षण से संबंधित जो विधेयक वर्ष 2023 में ही पारित होकर संविधान का हिस्सा बन चुका था, उसे फिर से तब क्यों लाया गया, जब कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया चल

रही है। यह बेवजह नहीं है कि इस संशोधन विधेयक को लाए जाने के समय को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। ऐसा लगता है कि इस विधेयक की जटिलता और उसके पारित होने के सामने खड़ी चुनौतियों की तस्वीर चूंकि लगभग साफ थी, इसलिए इसे राज्यों में जारी चुनावी प्रक्रिया के बीच महिलाओं का समर्थन हासिल करने वाले एक अहम मुद्दे के रूप में भी देखा गया। शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश के नाम संबोधन में भी यह साफ दिखा, जिसमें उन्होंने महिला आरक्षण से जुड़े इस संशोधन विधेयक के

पारित न होने के लिए विपक्षी दलों को जिम्मेदार बताया। मगर विधेयक में जिस तरह सरकार ने आरक्षण व्यवस्था को एन-परिसीमन और लोकसभा के विस्तार के ढांचे से जोड़कर पेश किया था, उसमें वह किस तरह के समर्थन की उम्मीद कर रही थी। महिला आरक्षण के प्रावधानों के साथ-साथ खासतौर पर परिसीमन के मुद्दे पर तमिलनाडु सहित दक्षिण भारत के राज्यों की जैसी प्रतिक्रिया थी, उसमें विपक्षी दलों के समर्थन या विरोध की तस्वीर एक तरह से पहले से साफ थी।

राजनीति में महिलाओं की राह मुश्किल, क्या आरक्षण बनेगा पितृसत्ता को तोड़ने का निर्णायक हथियार?

जनतंत्र में गजब की ताकत होती है। यह चीजों को विद्युत गति से उलट-पुलट कर देने की क्षमता रखता है। इसी क्षमता के कारण यह मुरझा तो सकता है, पर कभी मरता नहीं है। यह सिर्फ चुनाव की पद्धति या प्रशासन का तरीका मात्र नहीं है, बल्कि गैरबराबरी को समाप्त करने का सबसे सशक्त माध्यम है। यही कारण है कि स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए आरक्षण ने उन्हें 'मैं भी हूँ' और 'मैं भी कर सकती हूँ' का अहसास कराया। वोट तो पहले भी दे रही थीं, पर उनमें नेतृत्व करने का आत्मविश्वास अंकुरित नहीं हो पाया था। आरक्षण ने शिक्षित-अशिक्षित, गरीब-अमीर, सामंती सोच आदि की दीवारों को एक झटके में तोड़ दिया। आज हजारों की संख्या में महिला सरपंच हैं और अन्य स्थानीय निकायों में उनकी उपस्थिति है। महिला चेतना तब परिवार की राय के अधीन थी, अब नीतियों के निर्धारण, विकास के कार्यक्रमों और सार्वजनिक गतिविधियों में सशक्त हिस्सेदारी देखी जा रही है।

(राकेश सिन्हा)
लोकतंत्र का मूल भाव योग्यता की खोज और नेतृत्व की पात्रता का सुजन करना होता है। इसके इतर होने पर जाति धर्म, क्षेत्र, संप्रदाय, भाषा की संकीर्ण भूमिका बढ़ने लगती है। एक समय वह था और एक समय यह है। वर्षों पूर्व स्कूल की छुट्टी में जब मैं शहर से गांव गया तब एक कैलेंडर मेरे पास था। उसमें गाड़ी चलाती हुई एक महिला की तस्वीर थी। मेरे पड़ोस की एक नवविवाहिता, जो घूंघट में थी, उसे देखकर विस्मय कर रही थी। समय बीता। कुछ वर्ष पूर्व गांव में जब था, तो वही महिला स्थानीय निकाय की उम्मीदवार थी और अपने लिए घर-घर जाकर वोट मांग रही थी। उन्हें देखकर पुरानी बातें मेरे स्मृति-पटल पर उभर कर सामने आ गईं।

जनतंत्र में गजब की ताकत होती है। यह चीजों को विद्युत गति से उलट-पुलट कर देने की क्षमता रखता है। इसी क्षमता के कारण यह मुरझा तो सकता है, पर कभी मरता नहीं है। यह सिर्फ चुनाव की पद्धति या प्रशासन का तरीका मात्र नहीं है, बल्कि गैरबराबरी को समाप्त करने का सबसे सशक्त माध्यम है। यही कारण है कि स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए आरक्षण ने उन्हें 'मैं भी हूँ' और 'मैं भी कर सकती हूँ' का अहसास कराया। वोट तो पहले भी दे रही थीं, पर उनमें नेतृत्व करने का आत्मविश्वास अंकुरित नहीं हो पाया था। आरक्षण ने शिक्षित-अशिक्षित, गरीब-अमीर, सामंती सोच आदि की दीवारों को एक झटके में तोड़ दिया। आज हजारों की संख्या में महिला सरपंच हैं और अन्य स्थानीय निकायों में उनकी उपस्थिति है। महिला चेतना तब परिवार की राय के अधीन थी, अब नीतियों के निर्धारण, विकास के कार्यक्रमों और सार्वजनिक गतिविधियों में सशक्त हिस्सेदारी देखी जा रही है। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का महिला आरक्षण का आग्रह चेतना को स्थानीयता के पिंजरे से बाहर निकालकर उसे राष्ट्रीय क्षितिज पर लाने का उपक्रम है। यों महिलाओं की भागीदारी पहले भी रही है। सुचेता कुपलानी उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री बनीं। इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री रहीं। संविधान सभा की सभी पंद्रह महिलाएं पूर्णिया बनजी से लेकर एन्री मार्स्करेने तक की पृष्ठभूमि कुलीन थी। जमीनी प्रतिनिधित्व का विषय तब मस्तिक में भी नहीं था। इसलिए आम महिला की चेतना को इस संक्षिप्त और सांकेतिक भागीदारियों से जगाया नहीं जा सका।

राजनीति में प्रवेश, पुरुषों के लिए सामान्य बात ही नहीं, उनका 'पुरुषार्थ' माना जाता है, तो

महिलाओं के लिए यह जोखिम उठाने वाला हो जाता है। इसलिए भागीदारी प्राप्त करने में उन्हें अनेक बाधाओं को पार करना होता है। लोकसभा में महिला आरक्षण का प्रावधान राजनीति में व्याप्त पितृसत्तात्मक सोच और प्रभाव को सदा के लिए दफनाने वाला सुधारवादी से कहीं अधिक क्रांतिकारी कदम हो

रहस्योद्घाटन हुआ था कि शून्य से एक वर्ष की 597, एक से दो वर्ष के बीच के 494 नवजात शिशुओं को विधवा घोषित कर दिया गया था। यह संख्या बढ़ती गई। इस जनगणना की रपट ने स्वामी श्रद्धानंद सहित अनेक राजनीतिकों को गहन समाज सुधार के लिए प्रेरित किया था। उस सच से इस सच तक पहुंचने में समाज ने अनेक

पहचान होती है। लोकतंत्र का मूल भाव योग्यता की खोज और नेतृत्व की पात्रता का सुजन करना होता है। इसके इतर होने पर जाति धर्म, क्षेत्र, संप्रदाय, भाषा की संकीर्ण भूमिका बढ़ने लगती है। पर यह जनतंत्र उसे धारण करने वालों में अपूर्णता का संकेत है। जिस समाज में राजनीति और जनता के बीच में



सकता है। यह सिर्फ कुछ सी महिलाओं का लोकसभा में प्रतिनिधित्व ही नहीं बढ़ाएगा, बल्कि जमीन पर हर तबके तथा हर वर्ग की महिलाओं को राजनीतिक विमर्श से जोड़ेगा। वे अब तक विमर्श की पात्र रही हैं, अब वे विमर्श में भागीदार बन रही हैं। महिला सम्मान और अस्तित्व, दोनों ही लंबे समय से विमर्श और सुधारवाद का हिस्सा रहे हैं। इतिहास साक्षी है कि समाज सुधार के प्रश्न पर विरोध के दो ध्रुवों के बीच भी एकता अनेकित नहीं मानी जाती है। 1829 में सती प्रथा के उन्मूलन में राखवादी राजा राममोहन राय और साम्राज्यवादी गवर्नर जनरल बेंटिकट के बीच पूर्ण सहमति थी।

भारत के सुधारकों ने 1921 की जनगणना में अभिव्यक्त तल्लू सच को समाज की अपनी आलोचना से कहीं अधिक समाज के लिए चुनौती और अवसर के रूप में देखा। उसमें

प्रयासों और सुधारों का साक्षात्कार किया है। महिला आरक्षण पर उत्तर-दक्षिण विभाजन का मुद्दा बेमानी है। भौगोलिक संरचना से भारतीय राज्य, समाज और लोकतंत्र अप्रभावित है। राष्ट्र एक जीवंत सांस्कृतिक इकाई है, जो मनुष्य शरीर की तरह है। यह यांत्रिक नहीं है। जिस तरह से शरीर का प्रत्येक अंग जीवन के लिए महत्वपूर्ण होता है, उसी तरह मेघालय से मध्य प्रदेश और अरुणाचल से आंध्र प्रदेश राष्ट्र, समाज और राजनीति का प्रतिस्पर्धी या विरोधभासी इकाइयां नहीं हैं। ऐसा होना भारत में संभव नहीं है। हमारी राष्ट्रीय चेतना सांस्कृतिक कारणों से अविभाज्य है। क्षेत्रीय अस्मिता को लोकतंत्र पर आरोपित करने का प्रयास लोकशाही के मूल अर्थ को खो देने जैसा है। संसद मूलतः कानून और कार्यपालिका के लिए जिम्मेदार एक संप्रभु संरचना है। एक सांसद जितना अपने क्षेत्र का प्रतिनिधि है, उससे अधिक उसकी राष्ट्रीय

गैर चुनावी, पर राजनीतिक रूप से सक्रिय पात्रों, संगठनों और सुधारकों को अल्पता होती है, वहां प्रतिस्पर्धी राजनीति बेलगाम हो जाती है। एक समय विनोबा भावे, जयप्रकाश, सिद्धराज ढुङ्गा, वीएम तारकुंडे जैसे लोग थे। वे चुनाव नहीं लड़ते थे, पर चुनावी राजनीति पर अंकुश की तरह होते थे।

महिला आरक्षण उसी योग्यता के सुजन का सशक्त माध्यम है। प्रश्न क्यों जरूरी है, उसे एक प्रचलित परंपरा से समझा जा सकता है। मेघालय की खासी जनजाति में पुरुषों की तुलना में महिलाओं की प्रधानता है, पर जब राजनीतिक भागीदारी का प्रश्न आता है, तब उनकी अपनी परंपरागत राजनीतिक संस्था 'दरबार' में यह पूरी तरह प्रतिबन्धित है। भले ही यह लोकसभा में अंकगणित के चक्रव्यूह में फंसे गया, पर इससे उपजने वाला विमर्श हमें मैत्रीय-गाणी तक पहुंचाने की क्षमता रखता है।

भारत में क्यों बढ़ रहा लीवर डैमेज का खतरा? इन 7 संकेतों को न करें नजरअंदाज

(दिव्यांशी भदौरिया)
वर्ल्ड लिवर डे पर जानें लिवर खराब होने के 7 प्रमुख लक्षण। यदि आपको लगातार थकान, त्वचा का पीलापन, या पेट में सूजन जैसे संकेत दिखें, तो यह गंभीर लिवर समस्या का संकेत हो सकता है, जिसकी तुरंत डॉक्टर से जांच करानी चाहिए।

आज यानी 19 अप्रैल को वर्ल्ड लिवर डे मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य है लिवर से जुड़ी बीमारियों के प्रति जागरूकता फैलाना, शुरुआती पहचान को बढ़ावा देना और लिवर के हेल्थ के लिए प्रति लोगों को सचेत करना है। इस साल की थीम है 'सॉलिड हैबिट्स, स्ट्रॉंग लिवर्स' जिसका मतलब है कि मजबूत आदतें, स्वस्थ लिवर है। भारत में लिवर की बीमारियां तेजी से पैर पसार रही हैं। सबसे डराने वाली बात तो यह है कि लिवर की बीमारी के लक्षण तब तक सामने नहीं आते, जब तक कि स्थिति बहुत गंभीर न हो जाए। इसी वजह से लिवर की बीमारियां जल्दी पता नहीं चलती हैं। हालांकि, कुछ संकेतों पर ध्यान देने से बीमारी का पता चल जाता है। आइए आपको इन संकेतों के बारे में बताते हैं।

लगातार थकान और कमजोरी महसूस होना: अगर आपको सबसे ज्यादा थकान महसूस होती है तो इसका पहला संकेत यही होता है। जब लिवर ठीक से काम नहीं करता है, तो ब्लड में टॉक्सिंस जमा होने लगते हैं। इससे दिमाग की काम करने की क्षमता और शरीर की एनर्जी प्राप्ति घटती है।

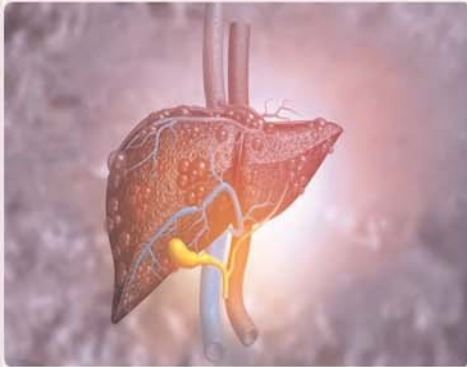
त्वचा और आंखों का पीला पड़ना : जब लिवर बिलीरुबिन को ठीक तरह से संभाल नहीं पाता, तो यह शरीर में इकट्ठा होने लगता है। इसके कारण त्वचा और आंखों में पीला रंग दिखाई देने लगता है, जिसे पीलिया का संकेत माना जाता है। आमतौर पर लोग इसी बदलाव को देखकर डॉक्टर से सलाह लेते हैं, लेकिन कई बार तब तक समस्या काफी गंभीर रूप ले चुकी होती है।

भूख में कमी और वजन का अचानक गिरना: अक्सर पाया जाता है कि लिवर खराब होने पर पाचन तंत्र पर सीधा असर दिखने लगता है। भारत की 7व से 32व आबादी फैटी लिवर से परेशान है। आज की जनरेशन में भी भूख लगने जैसे लक्षण आम होते जा रहे हैं, जो लिवर का समस्या का बड़ा संकेत है। पेट में दर्द या सूजन

ज्यादा जानें स्वास्थ्य फिटनेस पेट में तरल पदार्थ का जमा होना इस बात का संकेत होता है कि लिवर बुरी तरह प्रभावित हो चुका है। भारत में सिरोसिस के मामलों का एक बड़ा कारण अत्यधिक शराब का सेवन माना जाता है, जिसके चलते पेट फूलने और सूजन जैसी समस्याएं तेजी से बढ़ रही हैं।

गहरे रंग का पेशाब और हल्का मल: यदि आपके पेशाब का रंग गहरा है और मल का रंग असामान्य रूप से हल्का है, तो यह बाइल के फलों में अम्ल का रक्तस्राव हो सकता है। कई लोग इसे सिर्फ डिहाइड्रेशन समझकर इंगोर कर देते हैं, जो बाद में दिकत दे सकता है।

आसानी से चोट लगना या ब्लूडिंग होना: लिवर शरीर में खून को



जमाने वाले जरूरी तत्व तैयार करता है। जब यह अंग कमजोर पड़ जाता है, तो छोटी-सी चोट लगने पर भी अधिक रक्तस्राव होने लगता है या शरीर पर आसानी से नीले निशान उभर आते हैं। कई शोषों के अनुसार, भारत में अनेक लोगों को सिरोसिस की जानकारी तब मिलती है, जब उन्हें खून बहने जैसी दिकतें शुरू हो जाती हैं।

त्वचा पर खुजली होना: अगर बिना किसी रैशेज या दाने के शरीर पर खुजली होना लिवर की बीमारी का एक छिपा हुआ लक्षण हो सकता है। यह त्वचा के नीचे बाइल सॉल्ट्स जमा होने के कारण होता है, जिसे लोग अक्सर सामान्य त्वचा समझते हैं।

समय पर पहचान है जरूरी: आपको बता दें कि, लिवर अचानक से फेल नहीं होता बल्कि यह धीरे-धीरे खराब होता है और अक्सर इसमें दर्द भी नहीं होता है। इसलिए समय रहते हुए लिवर की बीमारियों के लक्षणों की पहचान करना बेहद जरूरी है। इस लेख के सुझाव सामान्य जानकारी के लिए हैं। इन सुझावों और जानकारी को किसी डॉक्टर या मेडिकल प्रोफेशनल की सलाह के तौर पर न लें।

चुनौतियों के चक्रव्यूह के बीच खड़ा बिहार का नया 'सम्राट'

सम्राट चौधरी का राजनीतिक उदय कोई आकस्मिक घटना नहीं है। यह उनके पिता शकुनी चौधरी की विरासत, और उनके स्वयं के आक्रामक संघर्ष, दशकों की राजनीतिक यात्रा, रणनीतिक धैर्य और समयानुकूल निर्णयों का परिणाम है। 16 नवंबर 1968 को मुंगेर के लखनपुर में जन्मे सम्राट ने बहुत कम उम्र में ही सत्ता का स्वाद चख लिया था। 1999 में रावड़ी देवी सरकार में सबसे कम उम्र के मंत्री बनने से लेकर आज मुख्यमंत्री की कुर्सी तक का सफर वैचारिक बदलावों और रणनीतिक फैसलों से भरा रहा है।

(योगेश कुमार गोयल)
सम्राट चौधरी का राजनीतिक उदय कोई आकस्मिक घटना नहीं है। यह उनके पिता शकुनी चौधरी की विरासत, और उनके स्वयं के आक्रामक संघर्ष, दशकों की राजनीतिक यात्रा, रणनीतिक धैर्य और समयानुकूल निर्णयों का परिणाम है। 16 नवंबर 1968 को मुंगेर के लखनपुर में जन्मे सम्राट ने बहुत कम उम्र में ही सत्ता का स्वाद चख लिया था। 1999 में रावड़ी देवी सरकार में सबसे कम उम्र के मंत्री बनने से लेकर आज मुख्यमंत्री की कुर्सी तक का सफर वैचारिक बदलावों और रणनीतिक फैसलों से भरा रहा है। राजद और जदयू जैसी क्षेत्रीय शक्तियों के साथ काम करने के बाद 2017 में भाजपा का दामन थामना उनके करियर का सबसे निर्णायक मोड़

साबित हुआ। भाजपा ने उनमें एक ऐसे पिछड़े नेतृत्व (ओबीसी) को देखा, जो न केवल संगठन में जान फूंक सकता था बल्कि राजद के 'माई' (एमवाई) समीकरण के



सामने एनडीए के 'लव-कुश' समीकरण को मजबूती दे सकता था। विशेषकर कुशवाहा समुदाय से आने के कारण सम्राट चौधरी भाजपा के लिए सामाजिक संतुलन का सबसे सटीक मोहरा साबित हुए। भाजपा ने उन्हें न केवल स्वीकार किया बल्कि प्रदेश अध्यक्ष जैसे महत्वपूर्ण पद देकर उनकी नेतृत्व क्षमता पर भरोसा भी जताया। यही भरोसा आज उन्हें मुख्यमंत्री पद तक ले आया है।

मुख्यमंत्री के रूप में सम्राट चौधरी की नियुक्ति के साथ ही बिहार की राजनीति में एक दुर्लभ संयोग भी जुड़ा है, जिन्होंने पहले उपमुख्यमंत्री की जिम्मेदारी संभाली और बाद में मुख्यमंत्री के पद तक पहुंचे। यह उपलब्धि उनके कद को तो बढ़ाती है लेकिन इसके साथ आने वाली अपेक्षाएं उनके लिए

एक मजबूत सांठगुंथ के ढांचे और भाजपा के शीर्ष नेतृत्व का अपेक्षा है लेकिन उन्हें अपनी 'आक्रामक छवि' को अब 'प्रशासकीय संयम' में बदलना होगा। मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने के बाद अब उनके हर फैसले की तुलना नीतीश कुमार के मानकों से की जाएगी। क्या वह उसी सहजता से महादलितों और अति पिछड़ों के हितों की रक्षा कर पाएंगे? क्या वह शराबबंदी जैसी पेचीदा नीतियों को लेकर जनता के बीच अपना स्पष्ट नजरिया रख पाएंगे? ये कुछ ऐसे सवाल हैं, जिनका उत्तर उनके कार्यकाल के शुरुआती सी दिन ही तय करेंगे। चुनौतियां केवल बाहर ही नहीं, गठबंधन के भीतर भी हैं। नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के बाद जदयू के भविष्य और निशांत कुमार के सक्रिय राजनीति में प्रवेश ने नई चर्चाओं को जन्म दिया है। जदयू के भीतर इस बदलाव को

लेकर एक दबी हुई छटपटाहट है। सम्राट चौधरी को यह सुनिश्चित करना होगा कि गठबंधन के सहयोगी दल खुद को उपेक्षित महसूस न करें। साथ ही, उन्हें भाजपा के भीतर भी उन वरिष्ठ नेताओं को विश्वास में लेना होगा, जो मुख्यमंत्री पद की दौड़ में पीछे रह गए। सम्राट चौधरी पर उनके पुराने विचारों, जैसे कम उम्र में मंत्री पद से हटाए जाने की घटना और उनके शैक्षणिक पहलुओं को लेकर विषय हमलावर रहेगा। एक मुख्यमंत्री के रूप में उनकी पेशेवर छवि और शुचितता पर उठने वाले सवालों का सामना उन्हें अपनी कार्यशैली से ही करना होगा। बिहार में 2025 का जनार्देश एक तरह से 'फेयरवेल मैसेज' जैसा रहा है, जहां जनता बदलाव की मानसिक तैयारी कर चुकी थी। सम्राट चौधरी के लिए सबसे बड़ी ताकत उनका ओबीसी समुदाय से होना और भाजपा आलाकमान का पूर्ण समर्थन है लेकिन उनकी राह का सबसे बड़ा कांटा 'नीतीश कुमार का साये' है। भाजपा ने अब तक बिहार में नीतीश कुमार का योग्य में राजनीति की है, अब उसे अपनी स्वतंत्र इमारत खड़ी करनी है, जिसकी नींव सम्राट चौधरी को रखनी है। यह सफर कांटों भरा है क्योंकि उन्हें न केवल विकास की रफ्तार बनाए रखनी है बल्कि बिहार की उस जटिल सामाजिक संरचना को भी साधे रखना है, जहां जाति की राजनीति कभी खत्म नहीं होती। सम्राट चौधरी की कहानी एक ऐसे संघर्षशील नेता की है, जिसने शून्य से शिखर तक का सफर तय किया है लेकिन मुख्यमंत्री के रूप में उनकी असली परीक्षा अब शुरू होने जा रही है। क्या वे बिहार को 'बीमार' छवि से पूर्णतः मुक्त कर 'विकसित बिहार' के संकल्प को सिद्ध कर पाएंगे? यह भविष्य के गर्भ में है मगर फिलहाल बिहार की सत्ता का यह नया 'चुनौतियों के चक्रव्यूह के बीच खड़ा' सम्राट चौधरी के पास अवसर भी है और चुनौती भी, अब यह उनके नेतृत्व पर निर्भर करेगा कि वे इस अवसर को इतिहास में कैसे दर्ज कराते हैं। (लेखक 36 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय वरिष्ठ पत्रकार और 'सागर से अंतरिक्ष तक' भारत की रक्षा क्रांति' सहित कई पुस्तकों के लेखक हैं।) (इस लेख में लेखक के अपने विचार हैं।)

स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक आशिष कुमार कंठले द्वारा कलरुप का भारत द्वारा अग्रदूत कॉम्प्लेक्स, रजबन्धा मैदान, भाजपा कार्यालय के पास, रायपुर, जिला-रायपुर (छ.ग.)-492001 से मुद्रित एवं वार्ड नंबर 18 बाजार पारा बेमेतरा पोस्ट व जिला बेमेतरा छ.ग. पिन कोड 491335 से प्रकाशित। संपादक आशिष कुमार कंठले समाचार चयन के लिए पी.आर.बी. एक्ट के तहत जिम्मेदार मो. नं. 7999238079, 7828658259, समस्त विवादों का निपटारा बेमेतरा न्यायालय होगा।